सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार/ Government of India

Diary No. DNO/26/CCPD/5785 **Dated:** 28/03/2026

Case No: DNO/26/CCPD/5785

In the matter of:

Mr Ajay Singh **...Complainant**

Versus

The General Manager, Northern Railway **...Respondent**

1. HEARING DETAILS

1.1. A preliminary hearing was conducted on 20.03.2026 in online mode, wherein the following parties/representatives were present:

Sl. No.	Name of the Parties / Representatives	On Behalf of
1	Mr. Ajay Singh	Complainant
2	Mr. Harijit Singh, APO	Respondent

2. RECORD OF PROCEEDINGS/ सुनवाई का विवरण

2.1 The Complainant, Mr. Inder Singh, filed a grievance dated 25.02.26 on behalf of his son, Mr. Ajay Singh, a person with 50% intellectual disability, regarding the long-pending settlement of a family pension. The Complainant submitted that as the legal guardian, he had repeatedly approached Northern Railway officials with all necessary documentation, including the disability certificate and proof of dependency. He sought the urgent intervention of the Court to expedite the pension processing to ensure lifelong care and financial support for his son.

2.1 शिकायतकर्ता, श्री इंदरसिंह ने अपने पुत्र श्री अजय सिंह, जो कि 50% बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability) से ग्रस्त हैं, की ओर से पारिवारिक पेंशन के लंबे समय से लंबित निपटान के संबंध में एक शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कानूनी अभिभावक के रूप में, उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र और निर्भरता के प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बार-बार उत्तर रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने अपने बेटे की आजीवन देखभाल और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

2.2 The Respondent submitted that the individual's disability certificate had been referred to the Central Medical Board. Based on that medical assessment, the Board determined that the individual did not meet the specific criteria required for a lifelong family pension.

2.2 प्रतिवादी (Respondent) ने प्रस्तुत किया कि व्यक्ति के विकलांगता प्रमाण पत्र को केंद्रीयचिकित्सा बोर्ड (Central Medical Board) के पास भेजा गया था। उस चिकित्सा मूल्यांकन के आधारपर, बोर्ड ने यह निर्धारित किया कि व्यक्ति आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए आवश्यक विशिष्ट मानदंडोंको पूरा नहीं करता है।

2.3 The Court observed that under Rule 75 (5) Clause (c) of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, eligibility for a lifelong family pension for a person with a disability is strictly contingent upon the individual being incapable of earning a living. In the present case, the Complainant's son is diagnosed with Mild Intellectual Disability. As there is no medical certification validating a total incapability of earning a livelihood, the Court finds that the eligibility criteria for the lifetime pension have not been met at this stage.

2.3 न्यायालय ने यह संज्ञान लिया कि रेलवेसेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75(5) खंड (c) के तहत, विकलांग व्यक्ति के लिए आजीवन पारिवारिक पेंशन की पात्रता पूरी तरह सेइस बात पर निर्भर है कि वह व्यक्ति जीविकोपार्जन (कमाईकरने) में असमर्थ हो। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के पुत्र "मंद बौद्धिक विकलांगता" (Mild Intellectual Disability) से ग्रस्तबताया गया है| चूंकिजीवि को पार्जन की पूर्ण अक्षमता की पुष्टि करने वाला कोई चिकित्साप्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिएन्यायालय का यह मानना है कि इस चरण में आजीवन पेंशन के लिए पात्रतामान दंड पूरे नहीं हुए हैं।

2.4 During the proceedings, the Court issued a stern caution to the Railway Authorities to clearly specify the grounds for acceptance or rejection of such requests to ensure transparency. The Court further advised the Railways to verify all current lifetime pensioners to ensure consistency and prevent the misuse of discretionary powers, ensuring that no eligible person is unfairly rejected while others are allowed. With these observations, the case stands disposed of.

2.4 कार्यवाहीके दौरान, न्यायालय ने रेलवे अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुरोधों की स्वीकृति या अस्वीकृति के आधारोंको स्पष्टरूप से निर्दिष्ट किया जाए। न्यायालय ने आगे रेलवे को सलाह दी कि वे सभी वर्तमानआजीवन पेंशनभोगियों का सत्यापन करें ताकि निरंतरता (consistency) सुनिश्चित हो सके और विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके,

Diary No. DNO/26/CCPD/5785 **Dated:** 28/03/2026

जिससे यहसुनिश्चित हो सके कि किसी भी पात्र व्यक्ति को गलत तरीके से खारिज न किया जाए जब कि अन्य को लाभ दिया जा रहा हो। इन टिप्पणियोंके साथ, मामले को निपटाया जाता है।

3. This is issued with the approval of the Commissioner for Persons with Disabilities.

3. यह दिव्यांगजन आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Yours faithfully,

(Praveen Prakash Ambashta)
Dy. Chief Commissioner